भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः नीतियाँ एवं प्रगति

डो मनोज सिंह
प्राचार्य
एस.एस. महाविद्यालय नगला सेवा कुरवारिया,बयाना, भरतपुर (राज.)

प्रस्तावना

पूर्वी ऐशियन देशों के विपरीत भारत के नीति निर्माता ने विदेशी निवेशकों के लिए रियायत के लालच देने को रोका। विदेशी निवेशकों ने अब तक दो युद्धकला वाली नीति अपनाई।

जिसे विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विदेशी फर्मो को आमंत्रित किया. साथ ही साथ विदेशी तकनीक के अनुमोदनों को घरेलू फर्मो में बढावा दिया। पिछले शोधों से यह दिखाता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढाने से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढी। जहॉ फर्म स्थित एक दूसरे से एक स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया पर मुकाबला करते हैं। प्रतिस्पर्धा बढते हुए दबाव के कारण अंक दर्जा नीचे रहा जिससे कि घरेलू फर्मो को चार्ज होने में मदद मिली। उनकी मिनी हुई उत्पादन में कमी आयी।

इसमें भारतीय उत्पादकों के लाभंश को नहीं बढाया। देशी फर्मो जो विदेशी फर्मो की तकनीक को अपनाते थे और उनकी नकल करते हैं. उन्हें विदेशी तकनीक उमड कहा जाता है क्योंकि इन फर्मो को उद्योगों में उमड तकनीक से काफी लाभ हुआ। उनको अतिरिक्त तकनीक चाहिए थी या तकनीक सीमा के नजदीक होना था। लेकिन वो उद्योग जहॉ उत्पादन की ज्यादा कियाऐ होती हैं वहॉ एक स्तर से उत्पादन के ज्यादा प्रक्रियाए होती हैं. उनको उर्ध्वता संयुक्त उद्योग कहा जाता है। पिछले शोधों से यह स्पष्ट करता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर सकारात्मक असर होता हैं। यह घरेलू और विदेशी फर्मो के लाभांश में तकनीक उमड का इन पर लागू होता हैं।

चावले की शोध में यह पाया गया कि विदेशी निवेश का उदारीकरण के समय में भारत ने निर्माता फर्मो में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया हैं यह बडी आश्चर्यजनक बात है कि एक स्तर के उत्पादन में मुकाबले करते हैं। एक हैरानी वाला नमूना है जो महसूस हो रहा है वो घटित होता दिख रहा है कि कई ढंगो से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढावा देने की नीति का बराबर पर तकनीकी उमड का प्रभाव हो रहा है जिससे कि देशी फर्मे तकनीक सीमा के नजदीक जा रही हैं। जबकि औद्योगिक अध्ययन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी तकनीक अनुमोदन उदारीकरण दोनों में सम्मिलित है। इससे यह आसान नहीं कि दोनों नीतियों में अन्तर किया जाए। ऐसा करने के लिए शोध को मोटर वाहन उद्योगों की गहराई से देखना पडेगा उसमें पाया गया है कि इस क्षेत्र में दो (उपकरण) विदेशी निवेश राज में फर्मो के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पडा है। भारत का अनुभव चीन से मिलाया जाता है. जबकि चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह को ज्यादा आकर्षित किया है। भारत में 1990 से पहले पोर्टफोलियो निवेश को भारत ने ज्यादा आकर्षित किया और बाजार की पूॅजीवादी अनुपात में इसकी सूची फर्मे है। जी.डी.पी. में काफी ऊॅचा किया और क्या भारतीय फर्मे उन विदेशों में विदेशी प्रत्यक्ष का बाहर प्रवाह लगभग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्गत के अनुकूल है भारत में विदेशी निवेश उदारीकरण, विदेशी तकनीक से। इस तरह व्यवहार करता है कि प्रत्यक्ष निवेश एक दूसरे से अभिन्न होने वाला कारण महत्वपूर्ण है। ऐसी नीति का असर बंधनीय है। ऐसी नीति से सादा संख्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह की आकृति से दूर है और कम से कम एक महत्वपूर्ण पत्र इस नीति की यह है कि इसका सकारात्मक प्रभाव उत्पादकता पर पडता है जो फर्मे. निर्माता करती है।

आर्थिक सुधारों के बाद अपनाई गई नीति के प्रमुख उद्देश्य

(1)निर्यात वृद्धि–*विश्व व्यापार में भारत के निर्यात को बढावा देने के लिए प्रत्यक्ष–विदेशी निवेश नीति में निर्यात वृद्धि से सम्बन्धित विभिन्न उद्देश्य किये गये है।*

(2) सामाजिक उत्तरदायी बाजार व्यवस्था की स्थापना–*प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति से बाजार व्यवस्था की स्थापना हुई है। इससे भारतीय व्यावसायिक इकाइयाँ पूरे विश्व में व्यवसाय करने लगी हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए राष्ट्रीय सीमाएं महत्वहीन हो गई हैं। भारतीय कम्पनियाँ जैसे इनफोसिस, टाटा कंसलटेंसी, विप्रो, टाटा स्टील आदि विश्व के कई देशों में व्यापार कर रही हैं।*

(3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना–*प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का यह भी उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। विदेशी कम्पनियॉ भारत में अपनी व्यावसायिक व उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर रही है। इससे भारतीयों के लिए रोजगार अवसर बढे हैं। जैसे विदेशी बीमा कम्पनियों मोबाइल कम्पनियों में बहुत से लोगो को रोजगार मिला है।*

(4) विदेशी पूंजी के माध्यम से औधोगिक एवं सेवा क्षेत्र का विकास करना–प्रत्यक्षविदेशी निवेश नीति का भारत में औद्योगिक एव सेवां क्षेत्र का तेजी से विकाश हुआ है। विदेशी कम्पनियों को दूरसंचार, बीमा, क्षेत्र, बैकिंग सेवा में आने से इन सेवा क्षेंत्रों में बहुत प्रगति हुई है। जैसे भारत में अब मोबाइल फोन बहुत सस्ते व काफी प्रचलित हो गए हैं।

(5)प्रतिस्पर्धा एवं कुशल उत्पादन व्यवस्था सुनिश्चित करना – प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का यह भी *उद्देश्य है कि इस नीति बहुत से घरेलू व विदेशी उद्यमियों ने भारत में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की हैं। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर टेलीकम्यूनिकेसन क्षेत्र में बहुत सी विदेशी व घरेलू कम्पनियों ने औद्योगिक इकाइयाँ लगाई हैं। जैसे रिलायन्स,. टाटा., हच,. एयरटेल आदि। इससे प्रतिस्पर्धा में बहुत वृद्धि हुई है। प्रतिस्पर्धा के बढने से कीमतों में कमी तथा क्वालिटी में सुधार आया है जिससे उपभोक्ता वर्ग लाभान्वित हुआ है तथा इनके जीवन स्तर में सुधार आया है।*

(6) निजी क्षेत्र पर अनुबंधित –प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों व निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने अपनी व्यावसायिक इकाइयाँ. उन्नत क्षेत्रों में स्थपित की हैं। ये उन क्षेत्रों में ही अपनी इकाइयाँ लगाते हैं जहॉ आधारभूत सुविधाऐ पर्याप्त मात्रा में हैं। पिछले इलाके में तो वे अपनी व्यावसायिक इकाईयाँ बिल्कुल भी स्थापित नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में बहुत वृद्धि हुई है। इसके कारण निजी क्षंत्र पर अनुबंधित किया है।

(7) **अर्थसंरचना को बढाना समग्र आर्थिक वृद्धि तीव्र करना** –वर्ष 1991 की विदेशी निवेश नीति से हमारी सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। इससे अर्थसंरचना को बढावा मिला है तथा आर्थिक वृद्धि भी तीव्र हुई है।

(8) **वैश्विक व्यवस्था में क्षेत्रीय भागीदारी बढाना** –विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में पिछले लगभग 15 वर्षो में एक बडा फेरबदल करते हुए यह फैसला डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्ल की 24 जनवरी. 2006 की बैठक में किया गया। अभी तक सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सम्भावनाओं से इनकार करती रही थी। सरकार के ताजा फैसले से रीवॉक व लुइस. क्टिान जैसी कम्पनियाँ भारत में अपने शोरूम स्थापित कर सकेंगी। अभी तक यह कम्पनियाँ अपने फ्रैंचाइजियों के माध्यम से भारत में उत्पादों की बिक्री करती थीं। इस प्रकार वैश्विक व्यवस्था में क्षेत्रीय भागीदारी अधिक बढी।

व्यूह नीति

निवेश आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न सभी नीतिगत निर्णय आर्थिक मामलों से सम्बद्ध कैबीनेट समिति की मंजूरी के लिए पेश किये जाऐंगे। आयोग की फरवरी 2006 में आई रिपोर्ट शीर्षक भारत के लिए निवेश रणनीति में यह बात उभर कर आई कि 8 प्रतिशत से ऊपर स्थिर विकाश हासिल करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में निवेश स्तर को जीडीपी का 28 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक बढाना होगा। आर्थिक विकाश की गति तेज करने के लिए आयोग ने'few national trust Areas'की पहचान की है। जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है– (2) पर्यटन. (2) ऊर्जा. (3) वस्त्र उद्योग. (4) अर्थव्यवस्था ज्ञान क्षेत्र तथा कृषि प्रशंसकरण. यह विशेष क्षेत्र पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेंगे जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

व्यूह नीति के उद्देश्य

(1) नीतिकरण प्रबन्ध।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

(3) अर्थव्यवस्था को नियन्त्रण मुक्त करने के लिए विभिन्न कानूनों में परिवर्तन।

(4) औधोगिक नीति में परितर्वन।

(5) विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी पूंजी निवेश के अन्त में वृद्धि।

(6) विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने पर बल।

सार्वजनिक क्षेत्र के 74 प्रतिशत तक शेयर विदेशी निवेशकों, संस्थागत निवेशकों,. म्यूचल फंड्स, जनता तथा श्रमिकों को बेचे गये। मार्च. 2007 तक 51,609 करोड रूपये के शेयर बेचे जा चुके हैं। कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के 100 प्रतिशत अंशों का भी विनिवेश किया गया है। इन उपक्रमों के अंशों को नीलामी– प्रक्रिया के द्वारा बेचा जाता है। इससे स्पष्टीकरण है कि व्यूह नीति ने सार्वजनिक में निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि की है।

नीति के प्रभावों की समीक्षाः

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का भारत के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पडा है। भारत में विदेशी निवेश का खास एक प्रभावशाली ढंग 1990 से रहा है। इसने विदेशी तकनीक को अपनाने के लिए बढावा दिया है। स्वयं घरेलू उद्योगों ने उसी वक्त ही इन उद्योगों को विदेशी निवेशों के लिए खोल दिया है इससे उदारीकरण के दो पक्ष बन गये।

(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक फण्ड नाम से जाना जाता है। जिसमें कि विदेशी फर्मे कम से कम 10 प्रतिशत देशी फर्मो में हिस्सेदारी करेंगे।

(2) विदेशी तकनीक समझौता ये इससे ज्यादा हाथ की दूरी का लेन–देन का विदेशी फर्मो में हिस्सेदारी है। इन दोनों पक्षों का आपसी महत्वपूर्ण इस तथ्य से देखा जाता है कि पिछले सुधार के समय में 1991 से 2005 तक अध्ययन में सम्मिलित है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजना, भारत सरकार ने मंजूर किये वो लगभग 19,000 और विदेशी तकनीक समझौता जो मंजूर किये वो सिर्फ 7600 थे।

राज्यवार विदेशी निवेश की प्रगति

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्यवार अनुमादन 1991 से 2004 तक के ऑकडे प्राप्त है और वो भी सिर्फ अनुमोदन के जिसे यह स्पष्ट होता है कि थोडे से राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ज्यादा हिस्सा को आकर्षित किया है। तालिका 2 में दर्शाये ऑकडो से स्पष्ट होता है कि 10 बड़े राज्यों में 68.63 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 20,00,06,510 इसके मुकाबले 10 निम्न स्तर केराज्यों ने मिलकर 1 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया। जहॉ भी क्षेत्रीय अलग–अलग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नमूने में अन्तरप्रवाह जो दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में जिन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया. दूसरे देश के भागों से। दक्षिण के तीन राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश ने 29.1 प्रतिशत कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्राप्त किया. जबकि 3 पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र. गुजरात और राजस्थान ने 33,74 प्रतिशत कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्राप्त किया और पॉच उत्तरी राज्य और दो यू.टी के राज्य जैसे जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाण, हिमाचलप्रदेश, उतराखण्ड, उतरप्रदेश, देहली. चंडीगढ आदि 22,08 कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्राप्त किया। केन्द्रीय क्षेत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और उडीसा 8.66 प्रतिशत कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्राप्त किया औरपूर्व क्षेत्र बिहार.झारखंड और पश्चिमी बंगाल ने 4,78 प्रतिशत कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्राप्त किया। इसके मुकाबले उत्तरी पूर्वी राज्य सबने मिलकर 0.03 प्रतिशत कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय में प्राप्त किया जो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का असमान वितरण भारतीय राज्यों में यह अनुमानित नहीं था। जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तरप्रवाह श्रेष्ठ आधारिक संरचना विकास और विकाश की तरफ हुआ और बडी बंदरगाहों और समुद्रीय किनारे का क्षेत्र का नजदीक होना एक खास महत्व रखता हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तप्रवाह में दिल्ली का हिस्सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन काफी ऊॅचा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन हुआ दिल्ली के लिए

जैसे उसकी स्थिति हैं। क्या दिल्ली क्षेत्र में प्लान्ट स्थापित करेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संकेन्द्रण भारत के उसी पॉकेटों में है। इसलिए क्षेत्रीय असमानता सुधारों के समय में कोई मदद नहीं कर सकें।

तालिका–1

राज्यवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन अगस्त 1991 से अगस्त 2004 तक

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदन की संख्या			विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन (रू.)	कुल का प्रतिशत
		तकनीक	वित्तीय	कुल		
1.	महाराष्ट्र	1313	3655	4972	3666024.15	14.78
2.	दिल्ली	306	2457	2763	303037.96	12.24
3.	तमिलनाडु	615	2041	2656	225826.40	9.12
4.	कर्नाटक	501	2085	2586	188184.32	7.60
5.	आन्ध्रप्रदेश	266	1010	1276	116091.37	4.59
6.	गुजरात	566	658	1224	111765.07	4.51
7.	मध्यप्रदेश	73	170	243	92714.08	3.74
8.	उड़ीसा	50	91	141	82293.13	3.32
9.	पश्चिमी बंगाल	198	481	679	77898.35	3.15
10.	उत्तरप्रदेश	277	534	811	48266.92	1.95
11.	हरियाणा	322	552	874	38751.56	1.56
12	राजस्थान	103	240	343	29112.04	1.56
13.	पंजाब	62	139	201	21241.53	0.86
14.	केरल	70	262	332	17806.31	0.72
15.	पांडिचेरी	42	88	130	12861.53	0.52
16.	हिमाचलप्रदेश	57	42	99	11741.45	0.47
17.	गोवा	66	210	276	8977.32	0.40
18.	बिहार	22	27	49	7397.05	0.30
19.	छत्तीसगढ.	31	17	48	6363.03	0.26
20.	झारखंड	54	27	81	1464.15	0.06
21.	उत्तराखंड	24	28	52	1256.49	0.05

भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तरर्प्रवाह का नमूना है। उससे स्पष्ट होता है कि कुछ ही राज्यों में संकेन्द्रण हुआ और राज्यों में कुछ ही जिलों में, ज्यादातर शहरी एकत्रीकरण में क्योंकि बड़ी घरेलू बाजार थी। शिक्षित श्रामिक काफी सस्ते मिलते हैं और बाजार की मित्रतापूर्ण नीति और कर प्रोत्साहन सम्बन्धित राज्य की मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत कोशिशें।विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो सम्बन्धित छोटे राज्यों में संकेन्द्र उसमें समृद्धि पैदा की। लेकिन मुश्किल से पूरे राज्य की गरीबी नहीं घट सकी और असमानता,(पाल और घोष) 2007 यह कहने के योग्य बात है कि महाराष्ट्र ने बड़े ऊँचे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तरर्प्रवाह में उसका ऊँचा गरीबी घटना 30.70 प्रतिशत था। जबकि इसके मुकाबले जम्मू और कश्मीर गरीबी घटना 5.4 प्रतिशत जिसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में नाममात्र का हिस्सा था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- Anand,J&Kogut,B:"Technological Capabilities of Countries, Firm Rivalry and Foreign Direct Investment", in, Journal of *International Business Studies*[hereafter JIBS], vol. 28, no. 3, 1997.

2- Culem, C.G.: "The Locational Determinants of Direct Investment Among Industrialised Countries", in, Europesn Economic Review, vol. 32, no. 4, 1988.

3- Dhar Biswajit and Roy, Saikat Chinha (1996), "Foreign Direct investment and domestic-investment Behavior: development countries Experience", Economic and Political weekly, September, p. 25-47.

4- Foreign Direct Investment in India. An Introspection by Om Prakash Kazipet and P. Krishnamachary Indian Journal of Public Enterprise, Allahabad, June 1994, pp. 73-83.

5- Lansbury, M & Pain, N: "Regional Economic Integration and Foreign Direct Investment: The Case of German Investment in Europe", in, National Institute Economic Review, No. 160, April 1997.

6- Ramchandram, K.S. Liberalisation and Foreign Investment, Yojana, New Delhi, June 15, 1992, p. 9.